REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 9 | JUNE - 2026

ऊर्जा संकट: अतीत और वर्तमान

डॉ. प्रशांत
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), बुंदेलखंड कॉलेज झाँसी.

सार संक्षेप

अमेरिका-ईरान भू-राजनीतिक संघर्ष भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में, भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 90% और एलपीजी का आधे से अधिक आयात करता है, जो कि संवेदनशील फारस की खाड़ी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है। होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी जैसी समुद्री बाधाएं वैश्विक ईंधन कीमतों में भारी वृद्धि का कारण बनती हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ता है। इसके तात्कालिक आर्थिक परिणामों में चालू खाता घाटा बढ़ना, घरेलू मुद्रास्फीति और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों का खतरा शामिल है । यह अध्ययन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले उतार-चढ़ाव से दीर्घकालिक आर्थिक विकास की सुरक्षा और,ऊर्जा विविधीकरण में तेजी लाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के विस्तार और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ।

कीवर्ड: ईरान युद्ध, होर्मुज जलडमरूमध्य, भारत, तेल संकट, ऊर्जा सुरक्षा , तेल संकट, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, चालू खाता, भू-राजनीतिक जोखिम ।

परिचय

1859 में जब अमेरिकी व्यापारी एडविन ड्रेक ने पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के पिटहोल सिटी में तेल की खोज की थी। तब से तब से विकसित होते-होते तेल की अर्थव्यवस्था आज इतनी विकसित हो चुकी है कि लगता है दुनिया की इकोनॉमी तेल से तर है । एडविन ड्रेक को यह चिंता थी कि उनका गैसोलीन कौन खरीदेगा लेकिन बात के वर्षों में आंतरिक दहन इंजन की खोज ने उनकी चिंता का जवाब दे दिया आज यही आंतरिक दहन इंजन दो पहिया वाहनों से लेकर कार, ट्रक, मालवाहक जहाज, जेट विमान में इस्तेमाल होता है । यही तेल हमारी दुनिया को गतिमान किए हुए हैं. हाइड्रोकार्बन आज संपूर्ण विश्व की एक तिहाई मांग ऊर्जा की माँग को पूरा करता है, यह एक तिहाई मांग कोयले से ज्यादा है और परमाणु बिजली और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त क्षमता का दोगुना है इतना ही नहीं यह हाड्रोकार्बन प्लास्टिक सेक्टर के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता

है। यही कारण है की समय-समय पर कई ताकतवर देशों ने तेल पर एकाधिकार, कार्टेल या मांग -आपूर्ति के समीकरण को अपने पक्ष में रखने की भरपूर कोशिस की है।

वर्तमान ऊर्जा संकट की जड़े 1973 में अरब-इजरायल संघर्ष से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। 1973 की घटनाओं ने यह साबित कर दिया था कि तेल उत्पादक देश के बीच राजनीतिक एकजुटता ऊर्जा आपूर्ति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता रखती है। वही 1979 की ईरानी क्रांति से पैदा हुई अनिश्चितता और उसके बाद 1980 में हुए ईरान-इराक युद्ध से अनिश्चितता और भी बढ़ गई जिसने आपूर्ति में बड़े पैमाने पर रुकावट आने का डर पैदा हो गया। ईरानी क्रांति, ईरान-ईराक युद्ध और 1991 के तेल संकट ने यह साबित कर दिया कि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक जोखिम कई आयामों वाला है इसमें न केवल जानबूझकर उत्पादन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावना है,बल्कि इस क्षेत्र के देशों आतंरिक शासन व्यवस्था में मौजूद अस्थाई स्थिरता भी इस स्थिति को और जटिल बनती है।

होर्मुज की नाकेबंदी और सकरे समुद्री रास्तो का सामरिक महत्व का इतिहास

होर्मुज की नाकेबंदी से तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं कई रूपों में प्रभावित हो रही है, लेकिन सकरे समुद्री मार्गों को को एक सामरिक रणनीति के तौर पर 1453 में महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय के साथ स्थापित की थी। कॉन्स्टेंटिनोपल और बीजान्टिन साम्राज्य का पतन मध्य युग के अंतिम दौर का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने रोमन साम्राज्य के प्रभावी अंत की शुरुआत की, यह एक ऐसा राज्य था जो लगभग 27 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और लगभग 1,500 वर्षों तक चला था। कई आधुनिक इतिहासकारों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन मध्यकालीन युग के अंत और प्रारंभिक आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक है। 1453 से पहले ओटोमन साम्राज्य मुख्य रूप से एक स्थलीय शक्ति था। 1453 के सफल नौसैनिक अभियान ने ओटोमन साम्राज्य के उदय को गति दी।1453 से लगभग चार सदियों तक ऑटोमन साम्राज्य भूमध्य सागर, काला सागर,लाल सागर,फारस की खाड़ी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करके एशिया और यूरोप के रास्तों पर राज किया। आटोमन साम्राज्य की ताकत सेना में नहीं बल्कि इन सकरे समुंद्री रास्तों में निहित थी। यूरोप की ताकतें ब्रिटेन,फ्रांस ,रूस, पुर्तगाल ,डच आटोमन से ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन ये शक्तियाँ जानती थी कि अगर यह साम्राज्य गिर गया तो ताकत का संतुलन बिगड़ जायेगा। इसी कारण यूरोपीय शक्तियाँ ऑटोमन को यूरोप का बीमार आदमी कहती थी और उसे जिन्दा रखती थी।

इसी साम्राज्य की छाया में ब्रिटेन,पुर्तगाल एवं डच पूरी दुनिया में अपनी औपनिवेशिक साम्राज्य खड़ा किया लेकिन ऑटोमन साम्राज्य का संतुलन उसके अपने भीतर की शक्तियों के कारण नहीं बल्कि बाहर की शक्तियों के द्वारा संभाली गई व्यवस्था थी। सभी यूरोपीय देश चाहते थे वह बना रहे अगर ऑटोमन बिखरता तो बड़ा युद्ध हो सकता था, बाहरी ताकतों के संतुलन के कारण यह लगभग 500 सालों तक चला और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब यह शक्तियों का संतुलन बिगड़ा बिगड़ा तो यही इलाका युद्ध का मैदान बन गया। ऑटोमन साम्राज्य के बाह्य संतुलन में पहले निर्णायक भूमिका ब्रिटेन की नौसेना ने समुद्री सकरे रास्तों को सुरक्षित करके की और उपनिवेशवाद के पतन के बाद अमेरिका ने खाड़ी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में अपने नौ सैनिक अड्डे बनायें भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा यहां रखा बड़ी, मात्रा में सैनिकों का जमावड़ो नें यह सुनिश्चित किया तथा खाड़ी के देशों को गारंटी दी इस धरती पर कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा।इसी सुरक्षा की गारंटी से पूरे विश्व को फायदा हुआ खासकर खाड़ी के देशों को। खाड़ी के देश तेल बेचकर अमीर बने अपनी कमाई को पश्चिमी देशों में निवेश किया। इन्हीं देशों के अमेरिका से पेट्रो-डॉलर समझौते ने डॉलर की बादशाहत कायम की। एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ी खाड़ी के देशों ने अपनी बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकाला, हालाँकि की मध्य-पूर्व में समय-समय पर युद्ध होते रहे लेकिन खाडी

के देशों में युद्ध के बजाय शांति एवं समृद्धि चुनी। इसी कारण पिछले तीन दशको में पूरे विश्व की संपत्ति खींचकर इस रेगिस्तान में आ गयी। लेकिन अमेरिका की सेल गैस की खोज से उसकी आत्मनिर्भरता और वर्तमान में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बनने बाद तथा चीन के बढ़ती महत्वाकांक्षा से वैश्विक संतुलन अमेरिका के हितों की विपरीत ज्यादा दिखता है, तो वह इस क्षेत्र में निहित समीकरणों को अपने ढंग से परिभाषित करना चाह रहा है।

वर्तमान अमेरिका -इजराइल और ईरान का संघर्ष और निहितार्ध

वर्तमान समय में जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो उसके पीछे या तर्क जोरों से उठाया की मध्य पूर्व में तनाव की वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है लेकिन असली खेल ऊर्जा का है या यूं कहें पूरे एनर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरी बार सत्ता हासिल की तो उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ इस बात का उल्लेख किया कि उनकी नीति का केंद्र एनर्जी नेशनलिज्म है,उनके ऐसे कहने के पीछे अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ाना नहीं था ,बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी नेटवर्क से था। इस एनर्जी नेटवर्क का सबसे ज्यादा फायदा मिडिल ईस्ट के उत्पादकों देशों ने और चीन ने उठाया था । अमेरिका के एनर्जी मिशन की जड़े 1973 के किम योपूर युद्ध से निकलती है 1973 में अरब देशों ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके कारण तेल की कीमत तीन चार महीना में ही तीन-चार गुना बढ़ गए थे यह घटना सिर्फ कीमत बढ़ाने की ही नहीं थी बल्कि इस घटना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। पश्चिमी देशों में महंगाई के साथ-स्टैगफ्लेशन आया। यही वह दौर था जब अमेरिका ने अपने भूभाग में तेल की खोज में निवेश को बढ़ाया और इस खोज में अमेरिका को शेल ऑयल मिला। इस शेल ऑयल ने 1980 के बाद अमेरिका के तेल आयात को खत्म कर दिया और इसी शेल ऑयल की बदौलत अगले चार दशकों में अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया।क्योंकि 1970 में अमेरिका मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर था तो इस संकट से निकलने के लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व से तेल को पेट्रो-डॉलर में एकीकृत किया और खाड़ी के देशों के साथ समझौता करके उनका सुरक्षा की गारंटी दी। जैस-जैसे अमेरिका में तेल आता गया पेट्रो-डॉलर की शर्त मजबूत होती चली गई और यह व्यवस्था लगभग 50 साल चली ,लेकिन एक संगठन जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है मजबूत हुआ और ओपेक प्लस से रूस जुड़ा इस कारण का कीमतों पर और नियंत्रण आ गया। इस घटनाक्रम में अमेरिका सबसे बड़ा तेल का उत्पादक तो बना लेकिन बाजार अभी भी ओपेक के पास रहा । 1990 में ग्लोबलाइजेशन शुरू होने के बाद भारत और चीन मध्य-पूर्व के दो बड़े तेल आयातक बने। वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण चीन ने इस खेल में सीधे दखल दिया चीन ने अपनी कूटनीतिक प्रयासों से सऊदी और इराक को दोस्त बना दिया इस दोस्ती के पीछे इसका मकसद पेट्रो-डॉलर को सीमित करना था । चीन पेट्रो-डॉलर की जगह पेट्रो-युवान को आगे बढ़ाया । धीरे-धीरे ओपेक के लिए अमेरिका की जरूरत खत्म होती गई जबकि अमेरिका अरब जगत की सावरेन पूंजी पर इस कदर निर्भर हुआ कि अगर मध्य-पूर्व के देश अपनी पूंजी का निवेश अमेरिका में न करें तो उसकी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल आ सकती है ,इन्हीं सब घटनाक्रमों के बीच जीवाश्म ईधन पर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण निर्भरता कम करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय प्रयास शुरू हुए और इस प्रयास में जीवाश्म ईधन के विकल्प के रूप में ग्रीन एनर्जी का समांतर विकल्प ढूंढने की कोशिश की गई। इस ग्रीन एनर्जी के बाजार में अमेरिका अभी कमजोर है । नई क्षमताओं को निर्मित और क्रियान्वित करने में चीन अमेरिका से काफी आगे जा चुका है। इस हालत में अब अमेरिका को हर हाल में तेल का बाजार चाहिए और इस तेल के बाजार में ओपेक सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ ओपेक की आलोचना करते हैं बल्कि उनकी मंशा यह भी है की तेल बाजार को बांटा जाए जिससे तेल की मांग बनी रहे और बढ़ती रहे। यह क्रिया तब तक चलती रहे जब तक अमेरिका ग्रीन

एनर्जी की क्षेत्र में चीन से आगे निकल जाने की स्थिति में नहीं हो जाता है। क्योंकि ग्रीन एनर्जी भविष्य की ऊर्जा है और उसका स्त्रोत हवा, सूर्य सब देशों के पास है इस कारण ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिका का कोई दखल नहीं है। चीन ग्रीन एनर्जी की सप्लाई चेन पर नियंत्रण करता है। ग्रीन एनर्जी की तुलना में पेट्रोलियम तेल दुनिया के कुछ ही भूभागों में केंद्रित है। ऐसे में अगर अमेरिका ऊर्जा के पुराने स्रोतों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो एनर्जी के बाजार में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा।

ऊर्जा पर नियंत्रण अमेरिकी कूटनीति का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आयाम रहा है, अमेरिका जिस समय ऊर्जा बाजार में सबसे बड़े उत्पादक के रूप में प्रवेश कर रहा है। उस समय ग्रीन एनर्जी के बढ़ते विकल्प के कारण जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की मांग कमजोर पड़ रही है। आज अमेरिका 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करता है यह उत्पादन सऊदी अरब से ज्यादा है और अमेरिका के तेल उत्पादन के इतिहास में सबसे अधिक है। जिस ऊर्जा तंत्र पर नियंत्रण के अमेरिका इस युद्ध में उतरा है उसके लिए ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में अपने पूर्व राष्ट्रपति वाइडन काल की ग्रीन एनर्जी नीतियों को छोड़ते हुए पर्यावरणीय नियमों में ढील दी, एलएनजी निर्यात पर लगी रोक को हटाया, अमेरिका के तेल उत्पादक क्षेत्र परमियन बेसिन और बैकेन बेसिन में तेजी से परमिट जारी किए 2040 तक लीज पर गैस और तेल बिक्री का रोड मैप तैयार किया, अर्थात अमेरिका में वह सारे उद्योग जहां हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होता है उन्हें पर्यावरण नियम नहीं माने पड़ेंगे तथा उत्सर्जन के नियमों में ढील दी गई एलएनजी के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया गया। परमियन बेसिन और बैकेन बेसिन एवं वह भूभाग जहां से तेल मिल आता है वहां से नए परमिट जारी कर दिए और 2040 तक लीज पर गैस और तेल की बिक्री का रोड मैप तैयार किया गया। इन कदमों से अमेरिका खुद को एनर्जी मार्केट खास कर ऑयल एलएनजी मार्केट में सप्लाई डोमिनेंस की स्थिति या आपूर्ति प्रभुत्व के रूप की स्थिति मिला दिया। दूसरा बदलाव मध्य-पूर्व के देशों से तेल संपत्ति को अमेरिका में लाने का रास्ता खोला जिसमें सऊदी अरब कतर यूएई के साथ-साथ कई दो ट्रिलियन डॉलर का समझौता किया। अमेरिका ने खाड़ी के देशों को वोइंग ,जहाज बेचा एनवीडिया के चिप्स बेचे तथा खाड़ी के देशों को दो ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में निवेश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने राजी कर लिया । डोनाल्ड ट्रंप एनर्जी पर नियंत्रण करने के लिए ईरान रूस और वेनेजुएला के तेल पर भी शिकंजा कस दिया, डोनाल्ड ट्रंप तेल उत्पादक देश पर शिकंजा कस कर सिर्फ कीमतों का ही खेल नहीं खेलना चाहते हैं, बल्कि वह पूरे एनर्जी तंत्र पर नियंत्रण चाहते हैं। जिसमें उत्पादक पर नियंत्रण और ग्राहक पर नियंत्रण दोनों दोनों शामिल है। रूस ईरान एवं वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाकर या सैन्य एवं वित्तीय दबाव डालकर उनकी पूरी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करके पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने से रोकता है। अगर उत्पादन क्षमता सीमित होगी तो बाजार में कीमत तय करने में अमेरिका को एक लाभ मिलेगा इस समय कीमतों का नियंत्रण ओपेक के हाथों में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात तेल के बड़े ग्राहकों पर कंट्रोल करने की है, जो दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहकों में भारत एक हैं इसी ग्राहक नियंत्रण की नीति में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका से तेल और गैस खरीदने के लिए बाध्य कर लिया।

खाड़ी सहयोग परिषद पर असर

ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का सभी खाड़ी देशों असर एक जैसा नहीं होगा कुछ देश इस झटके को आसानी से सह सकते हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले चोट उन्हें लगेगी जिन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं तटस्थ मध्य पूर्व के आधार पर बनाई थी। इस तटस्थता के आधार पर योजनाएं बनाने में खाड़ी सहयोग परिषद पहले स्थान पर आता है। पिछले 10 वर्षों में खाड़ी सहयोग परिषद के देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया है। खाड़ी सहयोग परिषद के देशों ने पांच ट्रिलियन से ज्यादा

सॉवरेन वेल्थ फंड जमा की है और यही फंड उनकी सुरक्षा के गारंटी देता है युद्ध की स्थिति में पूंजी का प्रवाह रुक सकता है,पिछले एक दशक में सऊदी अरब,कतर, कुवैत ने तेल पर निर्भरता कम करने का सपना देखा था तथा उनके भविष्य की योजनाओं में सऊदी विजन-2030,नियोम , रेड सी प्रोजेक्ट, यूएई का एआई लॉजिस्टिक हब, क्रिप्टो में इन देशों ने बड़ा निवेश करके फाइनेंस हब बनाना, तथा कतर के गैस ग्लोबल नेटवर्क में विस्तार की बुनियाद इस आधार पर रखी थी की खाड़ी के देशों में कोई युद्ध का संकट नहीं आएगा और खाड़ी में भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ स्थिर रहेगी। अगर युद्ध जारी रहता है तो बड़े प्रोजेक्ट की लागत बढ़ सकती है सऊदी अरब का राजकोषीय संतुलन तेल की ऊंची कीमतों पर निर्भर है इस प्रकार से खाड़ी सहयोग परिषद के देश का बजट तेल की ऊंची कीमतों से एकत्रित हुए राजस्व की ओर बढ़ सकता है लेकिन तेल की कीमतें अगर अस्थिर रहती हैं और निवेश घटता है तो खाड़ी सहयोग परिषद देश में डायवर्सिफिकेशन का दबाव आ सकता है। मिसाइलें अगर मध्य पूर्व के देश पर गिरती रहेगी तो निवेशक जोखिम का नया हिसाब -किताब लगाएंगे, शिपिंग पर बीमा प्रीमियम बढ़ाएंगे,जहाज की परिवहन लागत बढ़ेगी तथा विदेशी प्रतिभाएं यहां आने से हिचकिचाएंगी। अरब देशों की बाध्तया यह है कि अगर वे इस युद्ध में कूदे तो उनकी तरक्की बिखर जाएगी, इस कारण खाड़ी के देश इस युद्ध में शामिल होने से बच रहे है। अरब देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल की निर्भरता से बाहर निकालकर एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में काम कर रहे है। तकनीक, शिक्षा, पर्यटन और वित्त जैसे क्षेत्रों में निवेश इस रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस परिवर्तन को संभव बनाने तथा ईरान के हमलों का असर मिटाने के लिए ज्यादा संसाधन की आवश्यकता है। इसके लिए तेल उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। ओपेक की उत्पादन सीमा नीति के चलते ज्यादातर अरब देश अपनी उत्पादन क्षमता का पूरी तरह से दोहन नहीं कर पा रहे है। इस कारण ओपेक के भीतर लंबे समय से उत्पादन को लेकर असमानता और असंतोष रहा. इसी कारण यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का रास्ता चुना है। वैश्विक ऊर्जा बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर भू-राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बदलावों से प्रभावित होता रहता है। दीर्घकालिक प्रभाव इतने सरल नहीं हैं।ओपेक की भूमिका केवल कीमतों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने बाजार को स्थिर रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

चीन पर असर

भारत अमेरिकी दबाव में रूस के तेल को छोड़कर अमेरिका के तेल का सौदा कर रहा था तब रूस के तेल की सप्लाई चीन की ओर मुड़ रही थी, क्योंकि रूस के तेल के एशिया में दो बड़े खरीददार हैं, भारत और चीन ,रूस और चीन के बीच तेल का व्यापारी एक सामान्य व्यापार था लेकिन अब यह स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया है । पश्चिमी देशों में रूस के तेल पर प्रतिबंध के बाद रूस का तेल एशिया और उसमें भी ज्यादा बड़ा भाग चीन में जा रहा है 2025 में रूस ने 238 मिलियन बैरल तेल का निर्यात किया जिसमें भारत और चीन प्रमुख खरीददार थे लेकिन चीन अब रूस से 3 मिलियन वायरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल खरीद रहा है यह मात्रा पहले की तुलना में काफी अधिक है इस व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में नहीं बल्कि युवान और रूबल में हो रहा है रूबल और युवान का ट्रेंड है 2023 तक चीन और रूस के बीच 60% व्यापार अपनी मुद्रा में होने लगा था यह स्थिति तब आयी जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए यह जोन डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है इन दोनों देशों के बीच व्यापार ही नहीं बल्कि समान्तर करेंसी का ढांचा भी बना रहा है चीन तक तेल पहुंचने के लिए एसपीओ पाइपलाइन है दो पाइपलाइन और तैयार हो रही है इस कारण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम रहेगी चीन की रिफाइनारियां रूस के तेल पर ज्यादा निर्भर हो गई है और यह संबंध लंबे समय के लिए है इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में भी बदलाव हो रहे हैं शंघाई

इंटरनेशनल एक्सचेंज पर युवान में तेल की ट्रेडिंग होती है चीन में सिस्प नामक एक भुगतान प्रणाली बनाई गई जो स्विफ्ट का विकल्प और ऊर्जा प्रतिबंधों का असर कम करती है। सऊदी अरब भी युवान में तेल भुगतान पर बात कर चुका है यह दिखाता है कि कुछ देश डॉलर के अलावा भी अन्य मुद्राओं में ट्रेड करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के चोक पॉइंट पर असर डालकर चीन की तेल आपूर्ति को नियंत्रित करेंगे। वेनेजुएला का तेल अब चीन नहीं पहुंचेगा जिससे चीन पर तात्कालिक दबाव बनेगा लेकिन पश्चिम एशिया में चीन टकराव की तैयारी पहले ही कर चुका था उसके पास तीन सुरक्षा के विकल्प है पहला रूस से पाइपलाइन तेजी से बढ़ रही है तथा दो नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। दूसरा चीन के पास 1.02 ट्रिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है और तीसरा होर्मुज पर चीन की निर्भरता अभी भी एक तिहाई के आसपास है जो चीन के ऊर्जा जरूरत के हिसाब से बहुत बड़ी है इस तरीके की परिस्थितियों से निपटने के लिए चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल पर सख्ती करके अमेरिका को समझौते को लिए राजी करा सकता है हाल के वर्षों में चीन ने अपनी उर्जा निर्भरता के स्रोतों को बदला है इस कारण चीज की जीवाश्म पर निर्भरता घटकर 50% रह गई है और बाकी के लिए ग्रीन ऊर्जा की जरूरत पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

भारत पर असर

भारत की अर्थव्यवस्था 7% की सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बढ़ रही है। वर्तमान भू-आर्थिक परिस्थितियों में यह एक अच्छी विकास दर मानी जा सकती है लेकिन भारत की यह विकास दर ऊर्जा की स्थिर कीमतों पर आधारित थी। होर्मुज पर निर्भरता के मामले में भारत की स्थिति काफी संवेदनशील है। भारत की कच्चे तेल आयात पर निर्भरता 88% तक पहुंच चुकी है। जनवरी 2026 में करीब करीब 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का इंपोर्ट रहा। एक अनुमान के मुताबिक 2035 तक भारत की कच्चे तेल की मांग 8 मिलियन बैरल प्रति दिन तक जा सकती है, यह एक काफी बड़ा आंकड़ा होगा। अगर क्रूड ऑयल प्रति बैरल में $10 की बढ़ोतरी होती है तो चालू खाते का घाटा 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। लगातार आयात पर बढ़ती निर्भरता और कच्चे तेल की अस्थिर कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डाल सकती है।

चालू खाता घाटा एवं आयात बिल का बढ़ना

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से आयात की लागत बढ़ जाती है और आयातित बिल अनुमानो की तुलना में अरबो डॉलर बढ़ जाता है। यह बढ़ी हुई कीमत चालू खाते के घाटे को बढ़ाती है तथा यही घाटा भारत के निर्यात से होने वाली कमाई और तेल के आयात पर होने वाले खर्च के बढ़ते असंतुलन को दिखाता है। यह चालू खाता घाटा विदेशी मुद्रा पर भी दबाव डालता है क्योंकि भारत इन आयातों का भुगतान विदेशी मुद्रा में करता है। इसके कारण मुद्रा का मूल्य और गिरता है तथा विनिमय दर प्रभावित होती है इसके कारण यह प्रक्रिया आयातों को और महंगा बनती है। अगर यही प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहती है तो भारी क्षेत्र में एक ढांचागत असंतुलन पैदा हो सकता है।

ईंधन की कीमतें और महंगाई

आर्थिक क्रियाओ के नजरिए से तेल एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग आती है जिसके कारण तेल की बढ़ती हुई कीमतें उत्पादन से लेकर वितरण के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया भारत में परिवहन की लागतों के रूप में महंगाई में प्रकट होता है जब परिवहन लागतें बढ़ती हैं तो कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ाकर इस लागत का

बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं। इस बढ़ती महंगाई के कारण कम आय वाले वर्ग की जीवन यापन की लागत बढ़ती है लोगों की खरीदने की क्षमता घट जाती है और परिवारों की वास्तविक आय को भी घटा देती है।

राजकोषीय दबाव एवं सब्सिडी की दुविधा

भारत तेल आयात पर आधारित एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसे तेल की कीमतों के बढ़ने का एक ढांचागत दुविधा का सामना करना पड़ता है सरकार को यह चुनना पड़ता है कि वह अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ आम जनता पर डालें या ईंधन सब्सिडी या फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर उसे लागत का बोझ स्वयं उठाएं। अगर सरकार कीमती बढ़ती है तो उसका बोझ महंगाई के रूप में पड़ता है और अगर वह सब्सिडी देती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है। इससे पूंजी और सामाजिक खर्च के लिए उपलब्ध संसाधन काम हो जाते हैं राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकार की आय और व्यय का अंतर भी बढ़ता है इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है जिस कारण सार्वजनिक की वित्त की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है।अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में सिर्फ तेल और गैस की कीमतें नहीं बढ़ती बल्कि इसके कई और महत्वपूर्ण उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ता है।

खाद्य पदार्थ -पेट्रोकेमिकल से तेल और गैस के अलावा कृषि उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उत्पादन किया जाता है। उन उर्वरकों में यूरिया,पोटाश,अमोनियम फास्फेट प्रमुख है उर्वरकों की आपूर्ति बुवाई के मौसम में काम हो जाती है तो पूरा फसल चक्र भी कर सकता है। जिसके असर खाद्य सुरक्षा पर लंबे समय तक बना रह सकता है, जिसका दुष्परिणाम गरीब देश में कमजोर तबकों पर भुखमरी के रूप में सामने आ सकता है।

हीलियम - दुनिया की एक तिहाई हीलियम की आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है। हीलियम प्राकृतिक गैसों से निकलने वाला एक बाई-प्रोडक्ट है इस गैस का उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया में होता है। इसका उपयोग करके वाहनों घरेलू उपकरणों कंप्यूटर मोबाइल में प्रयोग होने वाले माइक्रोचिप के निर्माण में किया जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हीलियम गैस का उपयोग एमआरआई स्कैनर के मैग्नेट को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। अगर हीलियम की आपूर्ति बाधित होती है,तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा डाटा सेंटर ,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा इंडस्ट्री एवं चिकित्सीय उपयोग के लिए भी गंभीर स्थिति खड़ा कर सकती है। कोविड़ -19 के दौरान भी इलेक्ट्रानिक्स चिप्स की भारी कमी देखने को मिली थी लेकिन वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मॉडल विकसित करने और उन्हें लागू करने वाली कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रानिक्स चिप्स की मांग बहुत अधिक है। इस कारण वर्तमान जंग की स्थिति में उनके उत्पादन पर भी सोचनीय प्रभाव पड़ सकता है।

सल्फर - सल्फर जिसका प्रयोग खाद और धातु संस्करण में होता है। सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। जिसका इस्तेमाल तांबा कोबाल्ट और निखिल की प्रोसेसिंग में होता है तथा लिथियम के एक्सट्रैक्शन या निष्कर्ष में भी होता है। दुनिया की आधी सल्फर की आपूर्ति हार्मोन के रास्ते होती है अगर इसकी आपूर्ति बाधित होती है तो बैटरियों से कर्म दो इतिहास की उत्पादन में होता है सल्फर की आपूर्ति में बाधा से कीमतें बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं पर दबाव बनाएंगे ।

दवाइयां -पेट्रोकेमिकल से निकलने वाले पदार्थ जैसे मेथेनॉल और एथेन का उपयोग दवाइयां के उत्पादन में __महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में किया जाता है। भारत दुनिया के गैर ब्रांडेड जेनेरिक के निर्यात में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। अनुमानों के मुताबिक अगर आपूर्ति बातचीत रहती है तो घरेलू स्तर पर दवाइयां की कीमतें बढ़ सकती है और दवाइयां की उपलब्धता को भी प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मध्य पूर्व के तेल संकटों के साथ भारत के प्रभावित होने का इतिहास एक ऐसी ढांचागत कमजोरी का हिस्सा है। जिसे कभी भी पूरी तरीके से हल नहीं किया जा सका है। हर बड़ी तेल आपूर्ति बाधाओं 1973,1979 ,1990 ने भारत को आर्थिक नुकसान तथा भारी राजनीतिक कीमत भी वसूली और इस कारण भारत के नीतिगत फैसलों में उथल-पुथल मची लेकिन यह नीतिगत उथल पुथल भी इस ऊर्जा निर्भरता को पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं कर पायी। देश की तेल आयात पर निर्भरता पाँच दशकों में कम होने के बाद बजाय लगातार बढ़ी है। 1970 के दशक की शुरुआत के मध्यम स्तर की निर्भरता से आज उच्चतम स्तर की आयात निर्भरता परिलक्षित हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कई पैमानो पर और अधिक मजबूत और बड़ी हुई है ,लेकिन इसने अपने घरेलू उत्पादन की तुलना में तेल की खपत को कई गुना तेजी से बढ़ाया है और 2026 में तेल आयात का पर निर्भरता 1970 के दशक में अनुभव की गई किसी भी स्थिति को बहुत बौना साबित करता है ।

वर्तमान समय की ऊर्जा आपूर्ति संकट जो पिछले वैश्विक तेल आपूर्ति बाधाओं से मिली सीख के बावजूद, भारत में घरेलू उत्पादन को घटने देना और खपत तथा आयातो पर निर्भरता को बढ़ने देने में रणनीतिक विफलता का सामना किया है। यह कमजोरी सीधे तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जिसमें घरेलू तौर पर इस्तेमाल होने वाली गैस की लागत से लेकर यूरिया उत्पादन के माध्यम से कृषि आपूर्ति की श्रृंखला की स्थिरता तक सब कुछ प्रभावित करता है। भारत की रियायती दरों पर तेल प्राप्त करने की कूटनीतिक सफलताओं को अस्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है जो देश की अंतर्निहित संरचनात्मक कमजोरी को दूर किए बिना केवल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को बदलकर समाधान प्राप्त करने की कोशिश को दर्शाता है। भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में एक ठोस बदलाव की जरूरत महसूस होती है। जिसमें विस्तारित राजनीतिक भंडार, सरकारी तेल कंपनियों में सुधार,एकीकृत गैस नेटवर्क की आवश्यकता पर काम किया जाना चाहिए। वास्तविक आत्मनिर्भरता प्राप्त किए बिना भारत की आर्थिक संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और वैश्विक ऊर्जा शक्तियों के अधीन रहेगी।

REFERENCES :

1. Steve Coll 2012: Private Empire Exxon Mobile and American Power Pengvin Books
2. Matthew R. Simmons 2005: Twilight In The Desert The Coming Saudi Oil Shock And The World Economy JohnWiley & Sons. Inc
3. Donald W. Dareing 2022: Engineering Practice with Oilfield and Drilling Application JohnWiley & Sons. Inc
4. Daniel Yergin 1990: The Epic Quist for Oil, Money and Power Free Press New Delhi
5. Daniel Yergin 2020: The New Map: Energy , Climate , and the Clash of Nations Pengvin Books
6. रेजा सिंबर जून 2006: जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज ईरान एंड यूएस: एन्गेजमेन्ट ऑर कोंफ्रोंटेशन
7. परमा सिन्हा पलित 2004: स्ट्रेटेजिक एनालिसिस यूएस एंड ईरान : द चेंजिंग डायनामिक्स एंड द लइकेलीहुड ऑफ़ ए कनफ्लिक्ट
8. हर्ष वी पंत 2026: द यूएस एंड ईरान वॉर : हाऊ इट इज रिडिफाइनिंग द ग्लोबल आर्डर आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
9. किम घटास 2021: ब्लैक वेव

10. टॉम बॉवेर: द स्क्वीज़ ऑयल ,मनी एंड ग्रीन इन द 21स्ट सेंचुरी
11. https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/from-barrels-to-molecules-gulf-s-emerging-multi-energy-export-model
12. https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/the-global-costs-of-instability-in-the-strait-of-hormuz
13. https://www.orfonline.org/hindi/research/moscow-and-beijing-s-divergent-interests-in-the-middle-east-conflict
14. https://www.orfonline.org/hindi/research/a-maritime-turn-for-the-us-iran-conflict
15. https://www.thehindu.com/news/indias-energy-security-amid-conflicts/article70944392.ece
16. https://www.thehindu.com/opinion/lead/indias-energy-strategy-needs-price-correction/article71026084.ece#:~:text=Despite%20this%20turbulence%2C%20the%20crisis,by%20about%2025%25%20on%20average.
17. https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/can-indias-waste-solve-its-energy-crisis-diving-into-bioenergy-technologies/article70994226.ece
18. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/energy-crisis-indo-pacific-strait-hormuz-10615099/
19. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-lessons-of-past-oil-crises-have-not-been-fully-learnt-10591200/